बिहार सरकार

2010-2015

Road Map for Health Department

परिचय

राज्य मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2010–2015 के लिए अनुमोदित सुशासन के कार्यक्रम में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के 16 प्राथमिकाताओं को उल्लेख है । इन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सक्रिय है । वर्ष 2011–2012 में स्वास्थ्य विभाग को गैर योजना मद में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए कुल 1156.29 करोड़ एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए 510. 67 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ।

इसी प्रकार से योजना मद में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र को कुल 544.50 करोड़ की राशि प्रस्तावित है । इसमें से स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए 200.00 करोड़ रू0, चिकित्सा शिक्षा के लिए 344.50 करोड़ प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में केन्द्र सरकार से लगभग 1592..00 करोड़ की योजना प्रस्तावित होने की संभावना है । इस प्रकार कुल मिलाकर गैर योजना मद में 1700.00 करोड़ तथा योजना मद में लगभग 2000.00 करोड़ व्यय हेतु वर्ष 2011–2012 में उपलब्ध होंगे ।

सुशासन कार्यक्रम की प्राथमिकताओं के अनुरूप 28 जनवरी, 2011 से 28 फरवरी, 2011 तक स्वस्थ्य बिहार मुहिम के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य चेतना यात्रा का आयोजन किया जा रहा है । इसके अन्तर्गत राज्य में लगभग 11000 स्वास्थ्य उपकेन्द्र तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है । प्राप्त सूचना के अनुसार स्वास्थ्य चेतना के पहले सात दिनों में ही कुल 2,66,853 लोगों ने इन शिविरों में अपना ईलाज कराया। स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अब निरन्तर संचालित किया जायेगा ।

बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर 22 मार्च, 2011 से राज्य के सभी शून्य से 14 वर्ष के बच्चे तथा सभी किशोरी बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य गारंटी का कार्यक्रम भी प्रारंभ करने का प्रस्ताव है । इसके अन्तर्गत सभी बच्चों और किशोरियों का स्वास्थ्य जॉच किया जायेगा एवं आवश्यक रेफरल की व्यवस्था की जायेगी ।

प्रखण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मजबूत करने की कोशिश चल रही है एवं इस वर्ष सभी प्रखण्डस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी । जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, प्रखण्ड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञयों का पदस्थापन कर इन जगहों पर सर्जरी की व्यवस्था का प्रयास चल रहा है ।

राज्य के वर्तमान छः चिकित्सा महाविद्यालय में सुदृढ़िकरण का कार्य तेज किया जा रहा है । साथ–साथ चार नये चिकित्सा महाविद्यालय (आई0जी0आई0एम0एस0, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, गवर्मेन्ट महाविद्यालय, बेतिया एवं मधेपुरा) में भी एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई संचालित करने हेतु आवश्यक तैयारी की कोशिश की जा रही है ।

राज्य में चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परिचायकों की व्यवस्था एवं पारा मेडिकल की व्यवस्था में भी सुदृढ़िकरण किया जा रहा है ।

राज्य सरकार की कोशिश है कि आमजन तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके ।

प्राथमिकताएँ

राज्य में शिशु मृत्युदर, मातृ मुत्युदर और कुल प्रजनन दर को आगामी पॉच वर्षो में राष्ट्रीय औसत से बेहतर बनाया जाएगा ।

वर्ष 2009 के ऑकड़ों के अनुसार बिहार में शिशु मृत्युदर में 2008 की तुलना में चार अंकों की गिरावट आई है । शिशु मृत्यु दर अब घटकर 52 हो गयी है, जबकि राष्ट्रीय औसत 50 का है । मातृ मृत्युदर के ऑकड़े एक महिने के अन्दर जनगणना विभाग से प्राप्त होने की संभावना है । बिहार का कुल प्रजनन दर 3–9 था । वर्तमान वित्तीय वर्ष में परिवार नियोजन को प्राथमिकता दी गयी है तथा इस वर्ष लगभग 6 लाख नसबंदी होने की संभावना है । 2005 में मात्र 1 लाख नसबंदी बिहार राज्य में हुआ करते थे । इसी प्रकार आई0यू0डी0 (कॉपर्टी) का कार्यक्रम भी गति पकड़ा है और वर्तमान में 2,28,052 किया जा चुका है । सभी आशाओं को परिवार नियोजन हेतु निरोध तथा गर्भ निरोधक गोलियॉ उपलब्ध करायी जा रही है । हर गॉव में यह व्यवस्था 28 फरवरी, 2011 तक पूरी तरह कामयाव होगी । संस्थागत प्रसव में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है । राष्ट्रीय आकड़ों के बेहतर होने के लिए घर पर हो रहे जन्मों का भी पर्यवेक्षण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता से करने की आवश्यकता है, ताकि प्रसव स्वस्थ एवं सुरक्षित हो सके । अस्पतालों में ममता बहनो के रहने से प्रथम घण्टे स्तनपान, माता और बच्चे की देख–रेख में सुधार हो रहा है । सुधार की गति और तेज करने के लिए 28 जनवरी, 2011 से 28 फरवरी, 2011 तक राज्य के सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो तथा स्वास्थ्य शिविर हो रहा है । 10,000 से अधिक ऐसे स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से सुदूर घर तक पहॅूचाने की व्यवस्था की गयी है इससे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर कम करने में सफलता मिलेगी ।

कुपोषण की गंभीर समस्या को दूर करने के लिए बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए विशेष कार्यक्रम मिशन के रूप में चलाये जाएंगे ।

कुपोषण का विषय समाज कल्याण विभाग के अधीन है, फिर भी कुपोषण की गंभीर समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग से चन्द पहल किया जा रहा है । कुपोषण दूर करने हेतु बच्चों, किशोरी, बालिकायें और गर्भवती महिलाओं की देख–भाल करने की आवश्यकता है । ऑगनबाड़ी केन्द्रों के साथ मिलकर उप स्वास्थ्य केन्द्र के अतिरिक्त गॉव स्तर पर अप्रैल, 2011 से मुस्कान कार्यक्रम के अन्तर्गत मासिक स्वास्थ्य एवं कुपोषण दिवस, राजस्व ग्राम में मनाने का स्वास्थ्य विभाग विचार कर रहा है । कम उम्र में शादी में कमी, किशोरियों के बीच आई0एफ0ए0 गोलियों का वितरण, गर्भवती महिलाओं को बेहतर भोजन, जन्म लेते हीं स्तनपान से भी कुपोषण की समस्या कम हो सकती है । इस पर स्वास्थ्य विभाग समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर काम करेगा ।

राज्य में राष्ट्रीय औसत से ऊपर टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए ''मुस्कान एक अभियान'' कार्यक्रम को और सुदृढ़ किया जाएगा।

मुस्कान एक अभियान कार्यक्रम की सफलता से पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत 16 प्रतिशत से बढ़कर 54 प्रतिशत तक पहुॅचा है । ग्रामीण स्वास्थ्य चेतना शिविर के अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से अप्रैल, 2011 से प्रत्येक राजस्व गॉव में मासिक स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर भी टीकाकरण के कार्य को और अधिक मजबूत किया जायगा ताकि बिहार की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर हो । 23 से 27 जनवरी,2011 तक पोलियो का राउण्ड संचालित हुआ जिसमें अच्छी सफलता मिली ।

राज्य के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 24 घंटे कार्यरत बनाया जाएंगा

राज्य के सभी प्रखण्ड स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र को 24 घंटे कार्यरत किया गया है, ताकि 30 शय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित करने हेतु भवन आदि की स्वीकृति प्राप्त हो । भवन निर्माण विभाग द्वारा कतिपय कारणों से इसका कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। बिहार मेडिकल सर्विसेज अधारभूत संचरना निगम के माध्यम से भवन निर्माण विभाग से पैसा मिलते ही प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को किया जायगा । प्रखण्ड स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी स्वास्थ्य चेतना शिविर के माध्यम से पूरी तरह से कार्यरत किया जा रहा है । जिन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन आदि का निर्माण हो गया है तथा चिकित्सक एवं परिचायकों की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है वहॉ पर 24 घंटे सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है । अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष चिकित्सकों का पदस्थापन किया गया है ।

व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सकों के रिक्त पद सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर नियमित रूप से भरे जाएंगे ।

राज्य में लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ उप सम्वर्ग हेतु 2,132 चिकित्सको की नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग को पूर्व में अधियाचना भेजी गयी थी । वर्तमान में यह प्रक्रिया पूर्ण होने पर है तथा 44 मुच्छकों की पहली सूची नियुक्ति हेतु विभाग को प्राप्त हो गयी है । आशा है कि शिशु, सर्जरी तथा महिला रोग विशेषज्ञ भी इस प्रक्रिया से शीघ्र चयनित होकर अपना योगदान देंगे । इसके साथ–साथ अनुबंध के आधार पर नियुक्त चिकित्सकों जो दो वर्ष तक कार्य पूर्ण कर लेने पर 2008 नियमावली के अनुरूप उन्हें नियुक्त करने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की गयी है । लोक सेवा आयोग को 1510 सामान्य चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी गई है । अगले दो माह में संभवतः पूरा किया जायगा । इसके अतिरिक्त एक बार आयु सीमा में छूट देकर चिकित्सकों की नियमित नियुक्ति करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

इसी प्रकार से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सभी रिक्तियों सह–सहायक–प्राध्यापक के पदों पर नियमित रूप से अथवा अनुबंध के आधार पर भरने हेतु विभाग में प्रस्ताव विचाराधीन है ।

एलोपैथी के साथ–साथ आयुष विधा के तहत राज्य के सभी अस्पतालों में जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा एवं दवाईयाँ उपलब्ध करायी जाएंगी ।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों के लिए लगभग 1365 आयुष चिकित्सकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है । कुछ और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्व से तैयार किये गये पैनल में आवश्यकतानुसार कुछ और आयुष चिकित्सकों को अनुबंध पर शीघ्र नियुक्त किया जायगा । आयुष चिकित्सकों के लिए आयुष की दवाईयॉ भी उपलब्ध कराई गयी है ।

स्कूली बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाकर उनके स्वास्थ्य की जॉच, बच्चावार स्वास्थ्य कार्ड का संधारण, विटामिन–ए, कृमिनाशक (Deworm) की दवा जैसी सुविधाएँ उनहें तीन महीने में एक बार निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाएंगी ।

स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य जॉच का कार्यक्रम गैर सरकारी संगठन के माध्यम से संचालित हो रहा है । इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है । तद्नुसार ग्रामीण स्वास्थ्य चेतना शिविर के अन्तर्गत इस व्यवस्था के माध्यम से कार्ड निर्माण का कार्य पूरा किया जा रहा है । माननीय मुख्यमंत्री ने विभाग को बिहार दिवस के दिन (22 मार्च) राज्य के सभी स्कूली बच्चों वार्षिक स्वास्थ्य जॉच तथा कार्ड निर्माण हेतु प्राथमिकता पर नई योजना तैयार करने का आदेश दिया है । तद्नुसार व्यवस्था की जा रही है । कृमी नाशक हेतु निर्धारित तिथि को सभी बच्चों को एलवेन्डा जोल दिया जा रहा है ।

पोलियों उन्मूलन कार्यक्रम को और सघन रूप से लागू कर आगामी वर्षो में उन्मूलन के हर संभव प्रयास किये जाएंगे ।

23–27 जनवरी, 2011 तक पोलियो कार्यक्रम सफलता पूर्वक सम्पन्न किया गया ।

राज्य में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की कमी को देखते हुए प्रत्येक प्रमुख रोग हेतु कम से कम एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना आगामी पॉच वर्षो में की जाएगी ।

राज्य में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण में राजेन्द्र नगर अस्पताल में ऑख जॉच एवं राजवंशी नगर अस्पातल में हड्डी रोग बनाने हेतु अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के डा0 आजाद तथा डा0 कोतवाल से सम्पर्क किया गया है । शीघ्र अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के साथ एक MOU भी किया जायगा । दिनांक 17 फरवरी, 2011 को डा0 आजाद एवं डा0 कोतवाल पटना आ रहे हैं । राजेन्द्र नगर अस्पताल में नेत्र चिकत्सा हेतु यंत्रों के लिए साधन उपल्ब्ध करा दिया गया है। राजवंशी नगर अस्पताल के लिए साधन उपलब्ध है और यंत्रों के क्रय हेतु निदेश दिया गया है । इसके अतिरिक्त आई0जी0आई0एम0एस0, पटना को अच्छे अस्पताल की भागीदारी से विशिष्ट सुपर स्पेशलिटी सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है ।

राज्य से इलाज हेतु बाहर जानेवाले रोगियों की संख्या को घटाने के लिए राज्य के भीतर स्थित स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक बदलाव लाया जाएगा ।

इलाज हेतु राज्य के बाहर जाने वाले रोगियों संख्या घटाने हेतु अन्य स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने की कोशिश की जा रही है । निजी क्षेत्र में महावीर कैंसर संस्थान आदि द्वारा सुविधा में बढ़ोत्तरी कर बाहर जाने वाले मरीजों की संख्या को कम करने की कोशिश की जा रही है ।

राज्य मे तीन प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों का भवन निर्माण एवं पूर्ण रूप से संचालन सुनिश्चित किया जाएगा । साथ ही निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज लगाने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा ।

वर्द्धमान मेडिकल कॉलेज के भवन निमार्ण प्रारंभ करने की प्रक्रिया बिहार राज्य पूल निर्माण निगम द्वारा पूरा कर लिया गया है । बेतिया तथा मधेपुरा मेडिकल कॉलेज का DPR के निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है । इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु चर्चा के पश्चात् नीति निर्धारण किया जायगा ।

राज्य के वर्त्तमान मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से उनमें भवन, विशिष्ट उपकरण, प्रशिक्षित चिकित्सकों एवं पारा चिकित्सकों की चिकित्सीय सुविधाएँ दी जाएंगी ।

राज्य सभी वर्तमान चिकित्सा महाविद्यालयों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हेतु भवन, विद्युत, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से सम्पर्क कर सुधार की कोशिश हो रही है । सुनियोजित तरीके से सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में सुधार होगा । बिहार मेडिकल आधारभूत संचरना निगम को क्रियान्वित कर उपकरणों की खरीद, भवन निर्माण एवं खरीद की कार्रवाई की जा रही है । अपील, 2011 तक इसे पूरी तरह से कार्य करने की कोशिश हो रही है ।

वर्त्तमान में कार्यरत ए0एन0एम0, जी0एन0एम0 प्रशिक्षण स्कूलों का सुदृढ़िकरण कर सीटों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाएगी एवं नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी । ऐसे विधालय एवं कॉलेज स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

नर्सिग की सुदृढ़ीकरण के लिए योजना बनाई गयी है जो अनौपचारिक परामर्श के लिए भेजी गयी है। सरकार का आदेश प्राप्त कर इसमें सुधार किया जायगा ।

राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 शय्या वाले स्वास्थ्य केन्द्रों में उत्क्रमित किया जाएगा ।

प्रखण्ड स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 शय्या बनाने हेतु बिहार मेडिकल आधारभूत संचरना निगम के पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद निर्माण संभव हो जायेगा ।

राज्य में राजमार्गो के किनारे 9 (नौ) अत्याधुनिक ट्रामा सेन्टर की स्थापना की जाएगी ।

अत्याधुनिक ट्रामा सेन्टर के स्थापना का कार्य राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा विचाराधीन है।

जनसंख्या स्थिरीकरण के कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए जन–निजी भागीदारी के तहत कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित की जाएगी ।

जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं । परिवार नियोजना के कार्य में काफी तेजी आयी है और ऐसा विश्वास है कि राज्य के प्रजजन दर में तेज गति से कमी आयेगी ।